

संपादकीय

खुशी दवा है, इसे आदत बनाएँ एक अरब से ज्यादा मन क्यों बीमार हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी और द लैसेंटे में प्रकाशित वैश्विक रिपोर्ट ने दुनिया को झकझोर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में करीब 120 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहे हैं और पिछले 34 वर्षों में इनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। वर्ष 2023 में 17 करोड़ से ज्यादा स्वस्थ जीवन वर्ष मानसिक बीमारियों के कारण प्रभावित हुए। यह आंकड़ा मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को दर्शाता है। कभी मानसिक बीमारी को कमजोर मन की निशानी माना जाता था, लेकिन आज विज्ञान स्पष्ट कर चुका है कि मानसिक विकार किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। किशोरों और महिलाओं पर इसका बोझ विशेष रूप से चिंता का विषय है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और तनाव, चिंता तथा अवसाद जैसी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके बावजूद हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी गलतियाँ दोहराते हैं, जो हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित करती हैं।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, खराब नींद, सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल और निजी जीवन की परेशानियाँ मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही हैं। हम दिनभर स्क्रीन पर समय बिताते हैं, रात को दर तक जागते हैं और सुबह थकान के साथ उठते हैं। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत तिवेदी के अनुसार, जीवनशैली में बदलाव मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे रासायन मनोदशा, प्रेरणा और भावनात्मक जुड़ाव में भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य पुरा करने से मिलने वाला संतोष, अपनों का साथ, व्यायाम और हंसी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन आज हम वास्तविक खुशियों के बजाय मोबाइल की रील, लाइक और आभासी दुनिया में संतुष्टि तलाशने लगे हैं। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए जीवनशैली में छोटे बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं। नियमित समय पर सोना और जागना, प्रतिदिन 30 मिनट तेज चलना, योग करना और साइकिल चलाना उपयोगी है। संतुलित भोजन में फल, सब्जियां और दाल शामिल करना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना और सुबह की धूप में समय बिताना भी लाभकारी हो सकता है। परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठकर भोजन करना, मित्रों से मिलना और दूसरों की मदद करना भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है।

किशोरों में मानसिक परेशानियों का एक बड़ा कारण दूसरों से तुलना करना भी है। सोशल मीडिया पर हर कोई सफल और खुश दिखाई देता है। ऐसे में बच्चों को लगने लगता है कि वे पीछे रह गए हैं। उन्हें समझाना जरूरी है कि असफलता जीवन का हिस्सा है और हर समय खुश रहना आवश्यक नहीं है। हालांकि, उदासी लंबे समय तक बनी रहे तो विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। हम शरीर में दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन परेशान होने पर अक्सर चुप रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यह झिझक दूर करना जरूरी है। मानसिक परेशानी कमजोरी नहीं है और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना समझदारी है। खुशी बाजार में नहीं मिलती, वह हमारी आदतों और रिश्तों में बसती है। समय पर सोना, नियमित व्यायाम करना, अच्छा भोजन लेना, अपनों से जुड़ना और खुद के लिए समय निकालना मन को स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। खुशी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे फैसलों का परिणाम है। इन्हीं आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं।

आजकल

रणनीति का बड़ा टर्न, अब मुद्दा धर्म नहीं, आम आदमी कोर ग्रुप की बैठक से निकला नया मंत्र

राजनीतिक दल अपनी राजनीति की दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट नसीहत दी है कि अब हिंदू-मुस्लिम जैसे भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठकर आम आदमी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यह कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को नई भार देने की कोशिश है।

पिछले कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपसी मतभेदों और गुटबंदी में उलझ गए हैं। कार्यालयों में बैठकर राजनीति हो रही है और जनता से सीधा संपर्क टूट रहा है। इसी स्थिति को बदलने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने सख्त संदेश दिया है कि आपसी मतभेद भुलाकर संगठन के हित में काम करना होगा।

पार्टी अब केवल विपक्ष की नहीं, बल्कि देशभर में शासन की जिम्मेदारी निभाने वाली पार्टी है। ऐसे में जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। जनता अब नारे नहीं, हिसाब मांगती है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे सवालों के जवाब चाहती है। राष्ट्रीय महासचिव स्तर से मिले मार्गदर्शन का मूल भाव यही है कि पार्टी को शासन की जिम्मेदारियों के अनुरूप सोचना होगा। केवल विचारधारा के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। जनता के बीच रहकर उसकी रोजमर्रा की समस्याओं को समझना जरूरी है।

कार्यालयों से निकलकर घर-घर तक पहुंचने का निर्देश कार्यशैली में बड़ा बदलाव है। सभी संगठनात्मक जिलों में प्रवास बढ़ाने और घर-घर जाकर संपर्क बनाने पर जोर दिया गया है। जनसंघ के समय से लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़ना संगठन की मजबूत परंपरा रही है। उसे फिर जीवित करने की कोशिश हो रही है। पद और जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, लेकिन कार्यकर्ता का मूल कर्तव्य नहीं। संगठन सर्वोपरि है।

नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि पुरानी सफलताओं पर संतोष जताकर बैठने का समय नहीं है। जनता के मुद्दों पर सक्रियता बढ़ानी होगी। यह संकेत है कि पार्टी समावेशी राजनीति की ओर बढ़ना चाहती है, जहां हर वर्ग के आम आदमी को लगे कि पार्टी उसकी ही है।

यह केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि वैचारिक पुनर्संतुलन का प्रयास है। सत्ता आती-जाती है, लेकिन संगठन स्थायी होता है। संगठन तभी स्थायी रहेगा, जब वह आम आदमी के दुख-दर्द से जुड़ा रहेगा।

84 महादेव दर्शन यात्रा

शूलेश्वर महादेव : जब अहंकार ने ललकारा महादेव को, तब न्याय ने लिखी पतन की गाथा

.....**डॉ. नवीन आनंद जोशी**.....

चौरासी महादेव की यात्रा केवल देवदर्शन का पथ नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों से साक्षात्कार की आध्यात्मिक साधना है। इस यात्रा का प्रत्येक देवस्थान मनुष्य को अपने भीतर झाँकने और अहंकार, अन्याय तथा अविवेक से मुक्ति पाने की प्रेरणा देता है। शूलेश्वर महादेव की पौराणिक कथा भी ऐसा ही शाश्वत संदेश समेटे हुए है।

पौराणिक आख्यान के अनुसार, देवताओं पर विजय प्राप्त कर अंधकासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि विवेक पर अहंकार का आवरण चढ़ गया। उसने स्वयं को अजेय समझते हुए भगवान शिव को कैलाश छोड़ने का संदेश भेजा और माता पार्वती को अपने अधिकार में लेने की धृष्टता की। महादेव ने शांत भाव से उसकी चुनौती स्वीकार की। किंतु अंधकासुर ने शिव की शांति को दुर्बलता समझ लिया। यही अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना है-वह सामर्थ्य के मद में मनुष्य को अपनी सीमाएँ भुला देता है और विनाश की ओर बढ़ते कदम

नईदुनिया

हार की हताशा की सड़क पर खीझ

.....**दिलीप झा**.....

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके खिलाफ बिना सबूत के अनर्गल आरोप लगाना भी अपराध है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि विपक्षी दल चुनाव आयोग को तलब नहीं कर सकते हैं। हां, किसी को शिकायत है तो वह हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाना क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है?

भाजपा के इस आरोप में दम है कि क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि सबसे पहले राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे। तो क्या वह उनकी भूल थी? देश की जनता विपक्षी दलों से यह पछुना चाहती है कि केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या यहां भी वोट चोरी हुई है? तमिलनाडु में विपक्षी दल की सरकार बनी, तो क्या यहां भी वोट चोरी से सरकार बनी है? दरअसल, एक अखबार की रिपोर्ट पर हाय-तौबा मचाने वाली कांग्रेस ने उसी अखबार की 2012 में प्रकाशित एक रिपोर्ट को क्यों ठुकरा दिया था? निश्चित रूप से इस अखबार की विश्वसनीयता पर वर्षों से सवाल उठ रहे हैं, जो चौथे स्तंभ के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। यह कौन-सी नीति है कि जिन राज्यों में चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक है और हारे तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हाय-तौबा मचाने लगे। अराजकता फैलाने में संलिप्त विपक्षी दलों के नेताओं को देश देख रहा है और जनता के बीच उनकी भारी किरकिरी हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और राहुल गांधी दो जगहों से चुनाव जीते, तो क्या यह भी वोट चोरी से संभव हुआ है? इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा।

2024 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतकर भाजपा को पूर्ण बहुमत से दूर रखने में सफल रही, तो क्या उसने वोट चोरी की थी अथवा जनता ने उसे जिताया था? ऐसे में विपक्ष का यह रवैया उसे जनता की नजरों में गिरा रहा है। यह सर्वविदित है कि 1993 तक केवल देश के प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव

आयुक्त को चुनते थे। तो क्या यह सही था? वर्तमान में प्रधानमंत्री के अलावा प्रतिपक्ष के नेता और एक अन्य नेता मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करते हैं। तो क्या यह तरीका पहले से ज्यादा

पारदर्शी नहीं है? इस बात को एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। यह हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चुनाव आयोग मतदाता सूची की सफाई का काम कर रहा है, तो विपक्ष चिढ़ रहा है कि इसकी सफाई क्यों हो रही है। जबकि केरल के गुहमंत्री के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी यह स्वीकार किया कि केरल में एसआईआर के कारण वहां कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी भारी संख्या में फजी तरीके से मतदाता सूची में नाम डलवाकर मतदान करवा लेती थी। फिर ऐसे में एसआईआर को गलत ठहराने का झूठा नरैटिव राहुल गांधी क्यों गढ़ रहे हैं, यह जांच का विषय है। इसके पीछे कौन-सी शक्तियां हैं, जो भारत में अशांति लाना चाहती हैं? इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए।

जबकि 1952 से 2013 तक कांग्रेस के शासनकाल में 20 बार एसआईआर हुए हैं, तो इतना बवाल क्यों नहीं हुआ? गत दिनों राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ एंटी-इनकबेंसी क्यों नहीं है, तो उन्हें शायद पता नहीं है कि दिल्ली में लगातार 15 वर्षों तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। वहीं, बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं और उनसे पहले 35 वर्षों तक वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। तो क्या वहां भी फजी तरीके से सरकार बनी थी? उस समय कौन-से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे? इसलिए चुनाव आयोग और भाजपा सरकार को चोर कहने से पहले राहुल गांधी को इसका जवाब जरूर देना होगा कि आपके पास वोट

समुद्र में आग, त्यापार पर हमला और मानवता पर सवाल

जब युद्ध जमीन से निकलकर पानी तक पहुंच गया

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब केवल सीमा की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि फैलकर काला सागर तक पहुंच गया है, जिसे दुनिया ब्लैक सी के नाम से जानती है। वहां तीन व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं। इन हमलों में एक भारतीय नाविक घायल हो गया है और 30 भारतीयों को मुश्किल से बचाया गया है। यह खबर केवल एक टुर्घटना की खबर नहीं है, बल्कि इस बात की चेतावनी है कि आधुनिक युद्ध में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। पहले कहा जाता था कि समुद्र सबका है, लेकिन अब समुद्र भी युद्ध का मैदान बन गया है।

काला सागर दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से गेहूं, तेल और अन्य जरूरी सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है। यूक्रेन को दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है और रूस ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। जब इन दोनों देशों से जुड़े समुद्री व्यापार पर हमले होते हैं, तो उसका असर सीधे गरीब देशों की थाली पर पड़ता है। जिन तीन जहाजों पर हमला हुआ है, उनके नाम अल्फा वतन, एबल और अफ्रामैक्स रियो बताए गए हैं। ये जहाज किसी सेना के नहीं थे, बल्कि सामान ले जा रहे थे। इसके बावजूद इन्हें निशाना बनाया गया। इसका अर्थ है कि अब युद्ध में यह नहीं देखा जा रहा कि कौन सैनिक है और कौन व्यापारी। ड्रोन से हमला करना आसान और सस्ता हो गया है, इसलिए व्यापारिक जहाज भी निशाने पर हैं। एक जहाज पर सात भारतीय थे, जबकि एबल नामक जहाज पर 18 लोग सवार थे, जिनमें सात भारतीय शामिल थे। इनमें से एक भारतीय घायल हो गया, जिसे बुल्गारिया की मदद से वारना ले जाया गया और उसका इलाज चल रहा है। वहीं, अफ्रामैक्स रियो पर सवार सभी 23 लोग भारतीय थे और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। भारतीयों का सुरक्षित बचना राहत की बात है, लेकिन यह सवाल भी खड़ा करता है कि दुनिया भर के समुद्रों में काम करने वाले लाखों भारतीय नाविकों की सुरक्षा कौन करेगा? उनका जहाज टोपोगे, पलाऊ या लाइबेरिया जैसे किसी भी देश के झंडे वाला हो सकता है, लेकिन जान तो भारतीय है। युद्ध होने पर सबसे पहले यही लोग फंसते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सेना नहीं, केवल एक जहाज होता है। भारत ने इस घटना पर केवल निंदा नहीं की, बल्कि समाधान का रास्ता भी सुझाया है। भारत ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने, काला सागर से अनाज और ऊर्जा की आवाजाही जारी रखने तथा व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद करने की बात कही है। ये तीनों बातें किसी एक देश के पक्ष में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हित में हैं। भारत ने कहा है कि व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना गंभीर चिंता का विषय है और यह शांति तथा स्थिरता

के लिए खतरा है। भारत दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि युद्ध का अंत हथियारों से नहीं, बातचीत से ही संभव है। ड्रोन ने युद्ध का चेहरा बदल दिया है। पहले युद्ध में बड़ी मिसाइलों और टैंकों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब एक छोटा-सा ड्रोन भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। काला सागर में तेल टैंकर का आग की लपटों में

घिरना इसी खतरे को उजागर करता है। ड्रोन को रोकना मुश्किल है और वह कहीं भी हमला कर सकता है। यदि ऐसे हमले बढ़ते रहे, तो जहाज कंपनियां काला सागर में अपने जहाज भेजने से डरेंगी। बीमा महंगा होगा और अंततः आम आदमी को महंगाई के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब काला सागर से जहाजों की आवाजाही बाधित होगी, तो गेहूं और ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे दुनिया भर में कीमतें बढ़ने का खतरा रहेगा। अफ्रीका के कई देश यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर हैं। वहां आपूर्ति बाधित होने से खेती संकट गहरा सकता है। इसलिए काला सागर में तीन जहाजों पर हमला केवल तीन जहाजों की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के भोजन की सुरक्षा का सवाल है। भारत ने इसी चिंता को समझते हुए अनाज और ऊर्जा की आवाजाही जारी रखने पर जोर दिया है। सदियों से समुद्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता रहा है। यदि काला सागर में व्यापारिक जहाज सुरक्षित नहीं हैं, तो दुनिया के दूसरे समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे। आज हमला काला सागर में हुआ है, कल किसी दूसरे समुद्र में हो सकता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। भारत ने हमलों की निंदा के साथ समाधान का रास्ता भी सुझाया है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन स्थायी समाधान तभी निकलेगा, जब ऐसे हमले बंद होंगे। एक भारतीय नाविक का घायल होना उन लाखों भारतीयों की चिंता सामने लाता है, जो विदेशों में काम करते हैं और युद्ध जैसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। 30 भारतीयों को सुरक्षित निकालना राहत की बात है, लेकिन असली सुरक्षा तभी होगी, जब समुद्र में आग लगना बंद होगी और जहाज बिना डर के चल सकेंगे।

काला सागर में तीन जहाजों पर हमला और एक भारतीय का घायल होना केवल एक समाचार नहीं, बल्कि चेतावनी है। यदि युद्ध को समुद्र तक फैलने दिया गया, तो उसका धुआं दुनिया के हर घर की स्मॉट तक पहुंचेगा। ऊर्जा पर हमले रुकें, अनाज की आवाजाही जारी रहे और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बंद हो, तभी शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

(**नईदुनिया संपादकीय डेस्क**)

ही नहीं बचा है, तो फिर इसकी चोरी कैसे हुई? दरअसल, कांग्रेस इन दिनों हकीकत और जमीनी आधार को समझने से कोसों दूर चली गई है। इसके पीछे अनेक कारण हैं और इनमें सबसे बड़ा कारण कांग्रेस

की नीतियां हैं। देश में हो रहे राजनीतिक बदलाव को कांग्रेस नेता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे देश में जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। यही वजह है कि तमिलनाडु में स्टालिन, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के परिवार तथा बिहार में लालू प्रसाद यादव और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस के पतन का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उसकी तुष्टीकरण की नीति देश की जनता को पसंद नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय की अवहेलना और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर अल्पसंख्यकों को तक्ज्जो देना कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह बयान दिलवाया गया था कि इस देश की संपदा पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वहीं, अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना भी कांग्रेस की बड़ी गलती माना जाता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसका वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया और कांग्रेस वहां भी सत्ता से बाहर हो गई। विपक्ष जनता को गुमराह करने का गहरा षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस देश की जनता की मूल समस्याओं को लेकर आज तक सड़क पर कभी नहीं उतरी है। कांग्रेस देश में झूठा नरैटिव बनाकर किसी भी प्रकार सत्ता पर कब्जि होना चाहती है, लेकिन ऐसा अब इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि उसे सत्ता तक पहुंचाने वाले राज्यों में उसकी उपस्थिति पिछले 40 वर्षों से नागण्य है। गुजरात, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में

छोटे राज्यों का बड़ा खेल, सत्ता बचाने का नया नक्शा

इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट आ रही है, वह केवल पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की बात नहीं है, बल्कि सत्ता के गणित को बदलने की बात है। आर्मी चीफ असीम मुनिर देश के चार प्रांतों को 12 से 15 हिस्सों में बांटने की योजना पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से पंजाब और सिंध की ताकत कम होगी और इस्लामाबाद का दखल बढ़ेगा। यह वही पुरानी तरकीब है कि जब केंद्र को मजबूत करना हो तो सूबों को छोटा कर दो। छोटे प्रांत बनने से राजनीतिक ताकत बंट जाएगी और केंद्र की शक्ति बढ़ जाएगी। सेना को देश की राजनीति और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का गढ़ पंजाब प्रांत है। सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत होने के कारण यहीं से देश की सत्ता का गणित तय होता है। पाकिस्तान की आभी से ज्यादा आबादी पंजाब में रहती है, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मजबूत है। खैबर पखूनख्वा और बलूचिस्तान में केंद्र के खिलाफ पहले से ही नाराजगी है। 1947 के विभाजन के बाद से पाकिस्तान के प्रांतों में भाषाई और जातीय पहचान गहरी रही है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रांतों को बांटने से आम लोगों की समस्याएं कितनी दूर होंगी और सत्ता का लाभ किसे मिलेगा।

पाकिस्तान में फिलहाल चार प्रमुख प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पखूनख्वा और बलूचिस्तान। ग्रामीण पंजाब में लोगों को बुनियादी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बलूचिस्तान में भी दूरदराज के इलाकों तक सुविधाएं पहुंचाना चुनौती है। लेकिन पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई और कर्ज की समस्या केवल प्रांतों के बड़े आकार के कारण पैदा नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रांतों को बांटने से समस्याएं हल होगी या नई मुश्किलें पैदा होंगी।

छोटे प्रांत बनने से मुख्यमंत्री की राजनीतिक ताकत घट सकती है और सेना का प्रभाव बढ़ सकता है। छोटे प्रांत का मतलब नया प्रशासन, नया बजट और नई संस्थाएं भी हैं। नए सचिवालय, विधानसभा और हाईकोर्ट बनाने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी है। ऐसे में नए प्रांत बनाना आर्थिक समझदारी है या राजनीतिक मजबूरी, यह विचारणीय प्रश्न है। नाइजीरिया जैसे देशों में भी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया गया, लेकिन केवल राज्यों की

कांग्रेस की कमर टूट गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस केंद्र में 12 साल से सत्ता से बाहर है और फिलहाल तीन साल अभी और बाहर रहेगा। दूर-दूर तक 2029 के आने चुनाव में भी उसके सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। अब उसके पास न सत्ता है और न सत्ता का साथ। 1996 के बाद से किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कांग्रेस जिस चाहती थी, उसे प्रधानमंत्री बनाती थी और जब चाहे समर्थन वापस लेकर उसे सत्ता से हटा देती थी। लेकिन आजाद भारत में पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी गैर-कांग्रेसी सरकार के एक दल के बहुमत वाले प्रधानमंत्री बने। इसलिए राहुल गांधी की हताशा देश को समझ में आ रही है। यह कितनी विचित्र बात है कि असम के गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई लगातार

15 साल तक असम के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या राहुल गांधी को एंटी-इनकबेंसी की याद नहीं आई? अगर कोई राजनेता यह समझता है कि चुनाव आयोग उसे चुनाव जिता देगा अथवा उसके विरोधी को हरा देगा, तो उसे निश्चित रूप से राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसलिए यह सच है कि प्याले में तूफान उठाने से शहर नहीं डूबते। इतिहास गवाह है कि 1952, 1957, 1962, 1967 एवं 1971 के पांच लोकसभा चुनाव लगातार कांग्रेस जीती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एंटी-इनकबेंसी नहीं आई? दरअसल, राहुल गांधी वोट चोरी की जो मनोहर कहानियां लोगों को सुनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें देश की जनता सुनने की तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान बदलते हुए भारत की तस्वीरों को लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। 7 अक्टूबर 2026 को लगातार सत्ता में 25 साल, 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और पिछले 12 साल से देश के संकल्प पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यही वजह है कि मोदी पूरे देश की जनता के जेहन में ऐसे बैठे हैं कि उन्हें परास्त करना विपक्षी दलों के किसी नेता के सामर्थ्य से बाहर की बात है।

संख्या बढ़ाने से भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष जैसे समस्याएं समाप्त नहीं हों। इस सिद्धांत को भारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। यहां समय-समय पर बड़े राज्यों को छोटे हिस्सों में बांटने की चर्चा होती रही है। बड़ा राज्य अधिक लोकसभा सीटों, राजस्वभा में प्रभाव और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका के कारण केंद्र के लिए चुनौती भी बन सकता है, खासकर तब, जब वहां विपक्ष की सरकार हो। हालांकि, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के पीछे भाषाई, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी महत्वपूर्ण रही हैं। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने, जबकि 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। इन फैसलों के पीछे जनभावनाओं के साथ राजनीतिक

गणित भी रहा है। नए राज्य बनने से नई राजधानी, नई विधानसभा और नए राजनीतिक समीकरण पैदा होते हैं। लेकिन क्या छोटे राज्य विकास की गारंटी हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड के गठन के 25 साल बाद भी नक्सलवाद, पलायन और क्षेत्रीय असमानता जैसे चुनौतियां बनी हुई हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन जारी है, जबकि तेलंगाना में विकास के साथ कर्ज का सवाल भी मौजूद है। स्पष्ट है कि छोटा राज्य अपने आप विकास नहीं ला सकता। इसके लिए ईमानदार प्रशासन, पर्याप्त संसाधन और जवाबदेह शासन जरूरी हैं। मुनिर की योजना और विपक्षी राज्यों को बांटने की राजनीतिक सोच में समानता तलाशने पर सत्ता के केंद्रीकरण का सवाल सामने आता है। जब नक्शा जनता की जरूरतों के बजाय सत्ता की सुविधा से बनाया जाता है, तब आम लोगों की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। यदि नए प्रांत बनने के बाद भी स्कूल, अस्पताल और सड़कें लोगों तक नहीं पहुंचतीं, तो ऐसे बंटवारे का औचित्य क्या है? राज्यों को छोटा करना अपने आप में समाधान नहीं है। समाधान सत्ता के विवेकीकरण में है। यदि पंजाब में लोगों को सेवाओं के लिए दूर जाना पड़ता है, तो जिला स्तर पर अधिकार बढ़ाए जाएं, तहसीलों में अस्पताल बनाए जाएं और स्थानीय किराओं को पर्याप्त संसाधन दिए जाएं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान भी संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं से होना चाहिए। मुनिर की योजना पाकिस्तान में क्या गुल खिलाएगी, यह समय बताएगा। इतना तय है कि नक्शे पर लकीरें खींचना आसान है, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर करना कठिन। असली राजनीति नक्शा तोड़ने की नहीं, लोगों को जोड़ने की होनी चाहिए।

(**नईदुनिया संपादकीय डेस्क**)

उस मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें पद का मद सेवा को सत्ता में, धन का अहंकार संवेदना को प्रदर्शन में और सामर्थ्य का दंभ संरक्षण को शोषण में बदल देता है।[जो व्यक्ति अपने अधिकारों को दूसरों की गरिमा से ऊपर रखता है, वह भूल जाता है कि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है।

अन्याय का परिणाम हमेशा तत्काल दिखाई नहीं देता, लेकिन वह विश्वास, संबंधों और सामाजिक व्यवस्था को भीतर से खोखला करता है। चौरासी महादेव की यात्रा हमें यही स्मरण कराती है कि मंदिर में झुकता हुआ मस्तक तभी सार्थक है, जब जीवन में भी अहंकार झुके और आचरण में करुणा जागे।शूलेश्वर महादेव का शाश्वत संदेश यही है-शक्ति के साथ विवेक, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व और सामर्थ्य के साथ विनम्रता आवश्यक है। मनुष्य की महानता उसके पद या वैभव से नहीं, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के हित में कितना करता है।

यात्रा निरंतर जारी रहेगी...